'Lab and Land' Programme in Karnataka and Surrounding States

2192. SHRI K. MALLANNA :
SHRI LAKSHMAN MALLCK :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Council of Agriculture Research has adjudged the 'Lab and Land' programme in Karnataka and surrounding States such as Tamil Nadu and Kerala ; and

(b) if so, the details regarding the programmes and their performance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) No, Sir, However an Evaluation Committee has already been constituted to evaluate the Lab to Land project, phase I (1979 to 1982) and phase II (1982-84). The Committee has already started functioning and has evaluated the Lab-to-Land programme in Haryana, Delhi, West Bengal, Orissa, and States/ Union Territories of North Eastern region. The team is expected to visit Kerala, Karnataka and Tamil Nadu also in this connection.

(b) Question does not arise at this stage.

बिहार ग्रामीण रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन

2193. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या ये सभी योजनाएं बिहार में भी क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अल्प-रोजगार वाले लोगों को रोजगार देने के लिए जो दो मुख्य रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम ।

(ख) इन योजनाओं का ब्योरा बताने वाला एक संक्षिप्त नोट संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) जब कभी संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के विशेष मामले नजर आते हैं, तो उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के साथ तत्काल उठाया जाता है । इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आयोजना, समन्वय, मानिटरिंग आदि का कार्य जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों को सौंपा गया है जो स्वायत्त-शासी निकाय होती है । कार्यक्रम की